DAINIK BHASKAR, Online, 16.10.2021
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

NHRC में पहुंचा मनीष हत्याकांड: रामपुर के RTI एक्टिविस्ट दानिश खान ने दी थी याचिका, NHRC ने दर्ज किया मामला

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/mirzapur/news/rampur-rti-activist-danish-khan-had-given-a-petition-nhrc-filed-a-case-129025776.html

मनीष गुप्ता हत्या प्रकरण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामला दर्ज कर लिया है। रामपुर निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने गोरखपुर जिलाधिकारी, एसएसपी एवं संबंधित थाने के पुलिसकर्मियों के विरुद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज करने की याचना दी थी।

गोरखपुर में हुई थी हत्या

बता दें कि गोरखपुर जिले के एक होटल में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप रामगढ़ताल थाने के इंस्पेक्टर सहित छह पुलिस कर्मियों पर लगा है। इस मामले में यूपी पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी।

याचिका पर आयोग ने लिया संज्ञान

वहीं अब यह मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी दर्ज कर लिया है। रामपुर निवासी आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खान ने गोरखपुर जिलाधिकारी, एसएसपी एवं संबंधित थाने के पुलिसकर्मियों के विरुद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में मामला दर्ज करने की याचना दी थी। जिस पर आयोग ने संज्ञान लिया है।

हैदराबाद एनकाउंटरः आयोग की जांच में सामने आए पुलिस की ग़लतबयानी और झूठ

http://thewirehindi.com/190042/hyderabad-2019-encounter-inquiry-panel-exposes-cover-up-lies-in-official-narrative/

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या मामले में छह दिसंबर 2019 को चारों आरोपियों की मौत के बाद देशभर की मीडिया ने साइबराबाद के तत्कालीन पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण किया था.

इस कॉन्फ्रेंस में तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने अपराध के ग्राफिक सीक्वेंस का ब्योरा देते हुए पुलिस एनकाउंटर में चारों आरोपियों के मारे जाने का दावा किया था. पुलिस का दावा था कि सभी आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस फायरिंग में मारे गए, जिसे लेकर लोगों ने उनकी सराहना की.

लेकिन चारों आरोपियों की मौत के ठीक दो साल बाद इस मामले के वे तथ्य धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं, जिन्हें शुरुआत में पुलिस ने दबा दिया था.

जांच आयोग ने पुलिस एनकाउंटर के आधिकारिक नैरेटिव को खारिज कर दिया है, जिसके बाद मामले में पुलिस के एक के बाद एक झूठ सामने आ रहे हैं.

आयोग ने 11-12 अक्टूबर को तत्कालीन पुलिस आयुक्त सज्जनार से 160 सवाल पूछे और उनके झूठ को दर्ज किया. इन्हीं झूठ को अब तक गलतियों के रूप में परिभाषित किया गया था.

हथियारों और गोला-बारूद का कोई रिकॉर्ड नहीं?

आयोग ने जांच की शुरुआत सज्जार से पूछताछ के साथ की, जिस दौरान उनसे आरोपियों के एनकाउंटर में शामिल स्पशेल ऑपरेशन्स टीम (एसओटी) के गठन और उसकी निगरानी को लेकर सवाल पूछे गए.

हालांकि, सरकार के 2004 के आदेश में यह स्पष्ट है कि किस तरह से एसओटी का गठन किया जाता है, उनकी निगरानी और वे किसे रिपोर्ट करते हैं, इसके बारे में स्पष्ट ब्योरा है लेकिन फिर भी सज्जनार ने असफल तरीके से यह कहा कि इस टीम ने उन्हें रिपोर्ट नहीं किया बल्कि उनसे जूनियर अधिकारियों को रिपोर्ट किया था.

पुलिस मैनुअल के मुताबिक, सिर्फ उनकी मंजूरी के बाद ही टीम को हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं. हथियारों और गोला-बारूद का एक अलग रजिस्टर बनाया जाना चाहिए जिसमें हथियार देने का मकसद, इसकी समयावधि और हथियार जारी करने की तारीख दर्ज होनी चाहिए लेकिन इस मामले में थानों में हथियारों के रजिस्टर में गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों को हथियार जारी करने की कोई एंट्री नहीं है.

इस पर उन्होंने कहा था कि इसके लिए उन्हें उस अधिकारी से सवाल पूछने चाहिए जो इस तरह के रजिस्टर को तैयार करता है, यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है.

मामले की निगरानी
तत्कालीन पुलिस आयुक्त सज्जनार ने महिला डॉक्टर की मौत की जांच के लिए नौ टीमों का गठन किया था और उन्हें समय-समय पर केस की स्टेटस रिपोर्ट देने का निर्देश दिया था.

हालांकि, उन्होंने जांच की निगरानी से इनकार करते हुए दावा किया था कि उनकी भूमिका जूनियर अधिकारियों से नियमित ब्रीफिंग लेने तक सीमित थी. वह इससे सहमत नहीं थे कि वह निजी तौर पर मामले में एसओटी के सदस्यों को पहचानते हैं.

लेकिन उनके 30 नवंबर 2019 के मेमो से पता चलता है कि उन्हें आरोपियों की कस्टोडियल जांच के दौरान शादनगर के एसीपी का सहयोग करने और सुरक्षा के लिए मुस्तैद किया गया था.

यह भी पता चला कि उन्होंने (सज्जनार) ने आरोपियों को घटनास्थल (फायरिंग) पर ले जाने के लिए विशेष वाहन का भी समर्थन किया था. इसके साथ ही उन्होंने एस्कॉर्ट पुलिस को छह बड़े हथियार मुहैया कराने की मंजूरी दी थी.

उन्होंने आयोग को यह बताया कि एके-47 और एसएलआर जैसे बड़े हथियार पुलिस को मुहैया कराए गए थे लेकिन वे बलात्कार और हत्या का ऐसा कोई और मामला नहीं बता पाए जिसमें उन्होंने पहले भी इस तरह पुलिसकर्मियों को हथियार मुहैया कराए.

इकबालिया बयान के आधार पर प्रेस बयान
तत्कालीन पुलिस आयुक्त ने 29 नवंबर को प्रेस को आरोपियों द्वारा कथित तौर पर किए गए अपराध का ग्राफिक ब्योरा दिया लेकिन आयोग के समक्ष यह स्वीकार किया कि यह पूरी तरह से डीसीपी की ब्रीफिंग पर आधारित था.

उन्होंने शाम सात बजे प्रेस को संबोधित किया था और केस डायरी के अनुसार आरोपी ने रात 10 बजे तक अपना इकबालिया बयान पूरा दर्ज कराया. उन्होंने (तत्कालीन आयुक्त) प्रेस को संबोधित करने से पहले आरोपी का कबूलनामा पढ़ा तक नहीं.

उन्होंने फिर दावा किया कि उनके प्रेस बयान सीसीटीवी फुटेज और इकट्ठा किए गए अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित थे लेकिन उनका यह ब्योरा कि आरोपियों ने पीड़िता के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया था, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर नहीं हो सकता.

पीड़िता के अंडरगारमेंट्स, पर्स और कार्ड की बरादमगी के वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है. परिणामस्वरूप उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि उनकी प्रेस मीटिंग से पहले कोई वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं थे.

क्या उन्होंने यह नहीं सोचा था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपियों को पेश करने से पहले प्रेस के समक्ष आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके इकबालिया बयान को उजागर करना उचित नहीं है. जैसा कि उन्होंने दावा किया कि उनकी मंशा जनता से जानकारी हासिल करना था तो आरोपियों के बयानों को उजागर करने की जरूरत कहां महसूस हुई.

उन्होंने दावा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक बुलाई गई लेकिन आयोग ने अपनी विस्तृत पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में आरोपियों की तस्वीरों और अन्य जानकारियों के साथ कहा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को डीसीपी द्वारा बुलाया गया था.

उन्होंने अकेले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया लेकिन इस अवसर पर जारी किए गए लिखित प्रेस बयान की कोई जानकारी नहीं थी.

उन्होंने सहमति जताई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले आरोपी के इकबालिया बयान पर आधारित थी क्योंकि अन्य तीन आरोपियों के बयान दर्ज नहीं किए गए थे.

स्पेशल ऑपरेशन्स टीम

उन्होंने यह दावा करने की कोशिश की कि उन्होंने विशेष ऑपरेशन्स टीम (एसओटी) का गठन नहीं किया है और यह टीम उन्हें रिपोर्ट नहीं करती लेकिन उनके मेमो से यह पता नहीं चलता कि इस टीम को किसी अन्य द्वारा गठित किया गया था.

उनका यह दावा कि आरोपियों पर फायरिंग करने में शामिल एसओटी डीसीपी को रिपोर्ट करती थी लेकिन आयोग के वकील ने कई तरीकों से उनके इस दावे को खारिज किया है.

सबसे पहले उन्होंने दावा किया कि उन्होंने टीम को आरोपियों को गेस्ट हाउस में रखने की अनुमति नहीं दी और उन्हें आगे की पूछताछ के बारे में सूचित नहीं किया गया.

उनके इन दावों को जांच में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों के बयानों के जरिये स्पष्ट रूप से खारिज किया गया.

नियमों का उल्लंघन

सज्जनार ने दावा किया कि उन्हें छह दिसंबर को ही पता चला कि आरोपियों को फायरिंग (घटनास्थल) की जगह ले जाया गया था. वे घटनास्थल पर सुबह 8.30 बजे पहुंचे थे और वहां जांचकर्ता अधिकारी एसीपी सुरेंद्र के साथ दो से तीन मिनट रुके थे लेकिन उनसे कोई बातचीत नहीं की थी. वह मौके पर डेढ़ घंटे रुके थे लेकिन शवों के पोस्टमार्टम को लेकर पुलिस को कोई निर्देश नहीं दिए थे.

यह पूछे जाने पर कि उन्होंने अपने अधिकारियों को निर्देश क्यों नहीं दिए कि वे शवों को शिफ्ट करने से पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट के आने का इंतजार करें. इस पर उन्होंने कहा था कि तेलंगाना में एनएचआरसी के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की गई थी.

फौरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और खराब तरीके से गढ़े गए झूठ

तत्कालीन आयुक्त द्वारा आरोपियों की मौत को लेकर की गई दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आरोपियों के साथ जाने वाले पुलिसकर्मियों के पास हथियार थे लेकिन उन्होंने आयोग को बताया कि उनकी खराब तेलुगू होने की वजह से वे सही तरीके से अपनी बात नहीं कह पाए.

उन्होंने स्वीकार किया कि उनका यह बयान कि पीड़िता का सामान एक झाड़ी के पीछे से बरामद हुआ था, वह भी गलत था.

उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे इनकार किया कि पुलिस के हथियारों के सेफ्टी कैच को अनलॉक किया गया था लेकिन आयोग द्वारा मुहैया कराए गए वीडियो में उनका झूठ साबित हुआ.

उन्होंने (सज्जनार) सहमति जताई कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा गलती से कहा कि आरोपियों की डीएनए प्रोफाइलिंग कराई गई थी.

उन्होंने एक और गलत बयान यह दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया कि पीड़िता का सामान बरामद कर लिया गया है लेकिन तब तक ऐसा नहीं किया गया था.

उनके मुताबिक, उनकी खराब तेलुगू की वजह से यह गलती हुई हालांकि वह 20 सालों से तेलंगाना में काम कर रहे हैं.

उनके ये तर्क सफेद झूठ हैं क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी में अपने संबोधन में स्पष्ट तौर पर कहा था कि पावर बैंक और पीड़िता का अन्य सामान बरामद किया गया. इसके बारे में पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसा पत्रकारों की तरफ से धड़ाधड़ पूछे जा रहे सवालों के बीच गलती से हो गया.

उन्होंने इस पर भी विचार नहीं किया कि जांच और शवों का पंचनामा न होने के बावजूद चार भाषाओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना अनुचित था.

आधिकारिक रूप से मामले को दबाया गया

आयोग ने 21 अगस्त से 38 गवाहों से पूछताछ कर हजारों सवाल पूछे हैं. इन गवाहों में कार्यकारी और न्यायिक मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, फॉरेंसिक विशेषज्ञ और मामले से जुड़े लोग शामिल हैं. इनकी गवाहों के साथ मिलीभगत विश्वास से परे है.

उदाहरण के लिए, 30 नवंबर 2019 को कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने आरोपियों को 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया जबकि वह सिर्फ सात दिनों के लिए हिरासत में भेजने के आदेश दे सकते थे.

उन्होंने आरोपियों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसी तरह की कानूनी जरूरतों की परवाह नहीं की. सबसे अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट 11 अक्टूबर को आयोग के समक्ष स्वीकार किया था कि जब उन्होंने दो दिसंबर 2019 को आरोपियों की पुलिस कस्टडी के आदेश दे दिए थे तो उन्होंने आरोपियों को निजी तौर पर पेश होने पर जोर नहीं दिया. उनका आदेश पूरी तरह से कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश पर आधारित था.

FREE PRESS JOURNAL, Online, 16.10.2021
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

After secularism and patriotism, human rights have been redefined, writes Anil Singh

https://www.freepressjournal.in/analysis/after-secularism-and-patriotism-human-rights-have-been-redefined-writes-anil-singh

After secularism and patriotism, human rights too are sought to be redefined by this regime. Speaking at the 28th Foundation Day of the National Human Rights Commission on October 12, Prime Minister Narendra Modi said that human rights matter to people only after their basic needs are met. The entire nation thinks that the Lakhimpur Kheri incident, where the son of the Union minister of state for home allegedly mowed down four unsuspecting farmers, was an outrageous case of human rights violation but the PM implied that it has more to do with politics than with human rights.

In fact, he has not condemned the incident and refuses to give in to demands to sack the minister. Instead, he alleged that “some people are tarnishing the image of the country in the name of human rights violations through their selective behaviour”. Perverse as this may seem – even tantamount to condoning the crime – it is the PM’s statement that human rights are secondary to basic requirements that is astonishing.

Human rights are the basic rights and freedoms based on shared values such as dignity, fairness, equality, respect and independence which are defined and protected by law. The Protection of Human Rights Act, 1993, defines them as the “rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual guaranteed by the Constitution or embodied in the International Covenants and enforceable by courts in India”.

Different take

However, the PM has a different take on it: “When a poor man is struggling for his basic facilities like toilets, electricity, concerns of health and treatment, and if somebody goes to him and lists out his rights, the poor man will first ask whether these rights will be able to fulfil his needs. In order to provide rights mentioned in the documents to the poor, it is very important to fulfill their needs first. When their needs get fulfilled, the poor can channel their energy towards rights and demand them.

“And we all are also aware that when the needs are fulfilled, there is an awareness regarding the rights and as a result, aspirations also grow faster. The stronger these aspirations, the more strength the poor get to come out of poverty. After coming out of the vicious circle of poverty, he moves towards fulfilling his dreams. Therefore, when a toilet is built in the house of the poor person and there is electricity and gas connection; it is not just a scheme which is available to him. These schemes are fulfilling his needs, making him aware of his rights and instilling aspiration in him.”

The PM’s desire to deliver goods and services to the poor is laudable but he misses the point that human rights are independent of all other rights. You may give a man bread, butter and jam but in a feudal and casteist country like ours that is not enough for him to

live with dignity; his human rights are to be guaranteed and enforced by the state. The rule of the law is universally applicable.

Hathras, Kappan, Stan Swamy cases

The Hathras gang rape and murder of 2020 is a case in point. The UP cops cremated the 19-year-old victim in the dead of the night without the consent and presence of her family which was kept locked up in their house. The district magistrate threatened the family from speaking out on national TV. Kerala journalist Siddique Kappan who was on the way to Hathras was arrested under the dreaded UAPA along with seven other and continues to languish in jail. Had the Supreme Court not intervened to get him proper medical treatment, he would have met the fate of Fr Stan Swamy, the 84-year-old tribal activist who was arrested with a dozen other academics and activists for a 'plot to kill Modi' and who died in custody.

Kappan's case is not unique. According to Geeta Seshu, co-editor of the Free Speech Collective, there has been a sharp rise in criminal cases lodged against journalists in India for their work with the majority of the cases in BJP-ruled states. Her research shows that in the last decade, 154 journalists in India were arrested, detained, interrogated or served show-cause notices for their professional work and a little over 40 per cent of these instances were in 2020.

Of course, Modi supporters see nothing Orwellian in it. The 'andolan jeevis' themselves are to blame, they say. Hence, the PM's rant: "In recent years, some people have started interpreting human rights in their own way. Some people see rights violations in some incidents but not in other similar incidents. This type of mentality also causes great damage to human rights." And he ended with the dog-whistle: "The country also has to be careful with such people."

Attack on JNU

Meanwhile, it is okay for armed mobs to ransack the JNU, it is okay to pick up a 22-year-old environmental activist from her home in Bangalore and take her to Delhi to be interrogated for anti-national activities as apparent from a toolbox she had forwarded to protesting farmers. As for BJP Lok Sabha candidates raising slogans such as 'Desh ke gaddaron ko, goli maaro salon ko', it is standard practice. Talk of being selective.

And since it is okay to invoke Gandhi in all sorts of whitewash jobs, so why not here: "Our revered Bapu is seen as a symbol of human rights and human values not only by the country but the entire world. It is our privilege that we are taking a pledge to live up to those values and ideals of Mahatma Gandhi through Amrit Mahotsav."

Dr Kafeel Khan case

Was the government not selective and vindictive in the case of Dr Kafeel Khan, the whistle blower in the 2017 case where more than 60 kids died because of oxygen

shortage in Gorakhpur’s BRD hospital? Was the government not selective and vindictive when it arrested student activists such as Sharjeel Imam, Natasha Narwal, Devangana Kalita, Meeran Haider, Asif Tanha, Safoora Zargar, Gulfisha and Umar Khalid for speaking out against the Citizenship Amendment Act, 2019.

The PM denied the migrant labour crisis and the oxygen shortage but now he has converted these corona failures into human rights trophies: “Past experiences show whenever a major tragedy strikes such a huge population, it leads to instability in the society. But what India did for the rights of its common people proved all the apprehensions wrong.”

It is not as if there is great respect for human rights in the non-BJP ruled states in India. The Maharashtra State Human Rights Commission is defunct. No state government is willing to implement police reforms and everyone is happy at the way the Centre is throttling the Right to Information Act.

However, the PM’s speech on the Foundation Day is deeply disturbing. It shows his utter contempt for any discussion, debate or dissent in a democracy. He just does not acknowledge that the onus for protecting life and liberty is on the state, failing which it has to be challenged by human rights groups, the opposition and as the Lakhimpur Kheri case showed, even by the Supreme Court. Abusing them as ‘sickulars, libtards and anti-nationals’ and converting human wrongs into human rights is a dangerous trend.

KP Leader Chrungoo writes to UNHRC on selective killings of minorities in Kashmir

https://timesofindia.indiatimes.com/india/kp-leader-chrungoo-writes-to-unhrc-on-selective-killings-of-minorities-in-kashmir/articleshow/87049231.cms

In view of the recent targeted killings of minorities in Kashmir, senior BJP leader Ashwani Kumar Chrungoo took up the issue with the United Nations Human Rights Council (UNHRC). In his memorandum submitted to the president of the UNHRC, Geneva, Nuzhat Shameem, Chrungoo, a popular Kashmiri Pandit leader, said that Pakistan supported terrorists in Kashmir. “Last year also we had brought up the issue of killings of political grassroot representatives and other minority community members in the Valley to your notice. We earnestly request the Council to view this whole issue in perspective of the continued ethnic cleansing of Hindus and Sikhs in the valley,” the letter read. “National Human Rights Commission (of India) observed recently in this connection that, “the painful incidents of killing of civilians allegedly by the terrorists are a serious threat to the democratic fibre of the country and people’s right to life, liberty, equality and dignity,” Chrungoo wrote. “Targeted killings of those who are not Kashmiri Muslims is an attempt to keep nonMuslims out of the Valley. It is a gross violation of human rights of minority communities in the Valley, which must be stopped.”

The paradoxes of PM's human rights speech

https://www.deccanherald.com/opinion/the-paradoxes-of-pms-human-rights-speech-1040817.html

Addressing the foundation day programme of the National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday, Prime Minister Narendra Modi said, "Some people see human rights violations in some incidents but not in others. Human rights are violated when viewed via political spectacles." He said, "Selective behaviour is harmful to democracy" and that some people "try to dent the country's image in the name of human rights." While one could not agree more with the prime minister that selective outrage can be harmful to democracy, it is pertinent to point out that more than ever in the history of independent India, selectivity has been practised during his regime and leadership. Let's start with the most recent example, the Lakhimpur Kheri violence, in which the son of his cabinet colleague is the prime accused. It has been more than two weeks since the horrific incident of human rights violation, and the PM is yet to utter a single word on it. Contrast it to the PM taking barely an hour or two to tweet or issue a statement when some real or supposed human rights violations occur in the non-Bharatiya Janata Party (BJP) ruled states or in other parts of the world. Silence and selective outrage have been the hallmarks of the current dispensation. Hence, while listening to the PM speak, one wondered if he was talking about himself and the behaviour of his cabinet colleagues and party workers. Also Read | PM Modi cautions against selective approach to human rights Another subject that the PM spoke about at the event specifically and proudly was how his government bestowed "new rights" on Muslim women. Here again, his claim was both misleading and selective. Over the last seven years, the Modi government has been silent on important issues affecting Muslim women. Members of his party and others in the Hindutva ecosystem have actively violated Muslim women's rights across the country. This was the reason hundreds of women's rights activists and others denounced the Modi government's decision to commemorate the day of criminalisation of instant triple talaq as the "Muslim Women's Rights Day" in August. According to them, the passage of the anti-triple talaq law, which claimed to protect Muslim women's rights, "in reality, had a more sinister purpose – to show Muslim men their place in a new India." Moreover, they noted that the law was an abomination and nothing but a charade because no such law was needed to "protect Muslim women, or secure their rights" since the Supreme Court had already struck triple talaq down. They went on to add, "This government has remained silent as Muslims have been lynched, and its leaders have garlanded the lynchers." The BJP has, they said, "both at the Centre and through its state governments, determinedly "gone after" Muslims under myriad laws, both old, new and proposed – beef bans, anti-conversion, including the recent UP Prohibition of Unlawful Religious Conversion Ordinance, 2020, and its proposed UP Population Control Bill." They justifiably noted, "It has systematically tried to rob Muslims of their right to livelihood, and Muslim women of their agency." Furthermore, the government has remained silent on constant online and offline sexual violence and threat to Muslim women. For example, in the notorious "Sulli Deals" episode, Hindu right-wing activists sought to auction Muslim women's bodies online. One can list dozens of such blatant incidents of violations of human rights, if not hundreds, but the government has hardly taken any interest to fix them. It seems the prime minister and his party colleagues are more interested in image building than

actually fixing the problem and genuinely making India a human rights friendly country. It is not surprising that the government and its machinery spend more energy and money on image-making. Unfortunately, the NHRC, which is an independent body established by an act of Parliament, is increasingly and conveniently becoming the full-time public relations department of the government. More than anything, the speech of the NHRC chairperson Justice (retired) AK Mishra at the foundation day event is the latest testimony. It was nothing short of indulging in dog-whistle and dangerous on Justice Mishra's part to say it was inappropriate to call terrorists freedom fighters.

In other words, the NHRC chairperson was trying to convey that human rights activists are defending "terrorists." This is misleading and akin to putting human rights defenders' lives and liberty at further risks. The fact of the matter is human rights activists are not defending terrorists but those who are accused of such heinous crimes. There is a critical difference between the two as the right to defend the accused no matter how heinous is the alleged crime is enshrined in our constitution and all the international covenants on human and civil rights to which we are signatory. According to the fundamental provisions of Indian law, every person is innocent unless proved guilty beyond a reasonable doubt. And human rights activists are just upholding the rule of law. On the other hand, we have been witnessing on a regular basis that terrorists like Nathuram Godse, who was convicted beyond reasonable doubts for killing Mahatma Gandhi, is glorified. Justice Mishra had nothing to say about this dangerous trend. The NHRC chief was well within his rights to appeal to social service organisations and human rights defenders to strongly condemn political violence and terrorism, which engenders "fundamentalism". However, appeals like these will only have any tangible impact when the NHRC stops acting selectively. It has been noted how the apex human rights body swings into action when human rights violations and political violence are reported from the non-BJP ruled states; it does hardly anything substantial in incidents reported from the BJP-ruled states. Perhaps, the starkest contrast in this regard is between West Bengal and Uttar Pradesh.

Flawed, dangerous reading of human rights

https://www.deccanherald.com/opinion/first-edit/flawed-dangerous-reading-of-human-rights-1040924.html

The criticism made by Prime Minister Narendra Modi of selective reading of human rights issues and the linkages he has made between rights and duties and rights and basic needs are problematic, and will not promote the cause of human rights. On the 28th foundation day of the National Human Rights Commission (NHRC) last week, Modi cautioned against the "selective interpretation of human rights and using human rights to diminish the image of the country." But the Prime Minister is as guilty of selective flagging of human rights as others whom he accuses of that fault. He cited the enactment of the triple talaq law by his government to honour the rights of Muslim women but has been silent on the growing attacks on and suppression of constitutional and human rights in the country. His government and its agencies cannot escape responsibility for them. Political contestation of rights and values is natural in a democracy. It is not right to claim that looking at human rights through the political prism is their biggest infringement. Politics might actually make violations more visible, and take the right into the more active democratic conversation. The government should in any case not be selective, even if politicians tend to be so. The problem actually arises when the violation is judged on the basis of the identity of the victim and of the person who raises the issue. That risk has risen in the country of late. The statement that human rights are used to harm the country's image is dangerous and seems like a warning. From there, it is only a short step to saying that advocacy of human rights is anti-national.

The Prime Minister made other untenable propositions, too. He said the duties of a citizen were closely linked to human rights and they should not be discussed separately. But such a linkage would work against the rights of the citizen because the State, which is a powerful entity, would be inclined and well-placed to extract duties out of the citizen before respecting her rights. It should be noted that the Constitution originally had no provision for fundamental duties and they were incorporated into it in another time of authoritarian rule, the Emergency. Duties are important, but linking them with rights would give primacy to them and limit the salience of rights. Similarly, the linkage between the basic needs of people and human rights is unacceptable. The Prime Minister said that the government has acted well and done much to meet the basic needs of the people. But it's the people's right to have their needs met, and there can be no trade-off between needs and rights.